कार्यकारी सारांश
छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड चावल वितरण पर एक फैक्ट-फाइंडिंग यात्रा की रिपोर्ट 13-15 जून, 2022

राज्य के चार जिलों (कोंडागांव, बस्तर, सरगुजा और कोरबा) के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न सरकारी खाद्य योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल वितरण पर एक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट और कई पात्रताओं- धारक / "लाभार्थी", विभिन्न लाइन विभागों के फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, पीडीएस डीलर, चिकित्सा विशेषज्ञ, और राज्य और जिला स्तर पर वरिष्ठ सरकारी / कार्यकारी अधिकारी के साथ बातचीत का कार्यकारी सारांश निम्नलिखित है। एलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा किसान स्वराज) और रोज़ी रोटी अधिकार अभियान (आरटीएफसी) द्वारा आयोजित फैक्ट-फाइंडिंग यात्रा जिसमे सात सदस्यीय टीम शामिल थी (जिनमें से दो डॉक्टर हैं) 13 जून से 15 जून 2022 के दौरान आयोजित की गई।

आशा और आरटीएफसी की टीमों ने मीडिया रिपोर्टों से इकट्ठा किया कि राज्य के कुछ स्थानों में लोगों द्वारा "प्लास्टिक चावल" होने का दावा करते हुए फोर्टिफाइड चावल की शिकायत की गई थी। इसने छत्तीसगढ़ में फैक्ट-फाइंडिंग के प्रयास को प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाला राज्य है जहाँ एक समग्र वैज्ञानिक तर्क के बिना बड़े पैमाने पर न्यूनीकारी पोषण हस्तक्षेप शुरू करने वाले राज्य ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अन्य लोगों को इसके संभावित प्रतिकूल परिणामों से बहुत परेशान किया है। इससे पहले झारखंड में कई जगहों से ऐसी ही शिकायतें मिली थीं। झारखंड की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।

1. **एनीमिया में बढ़ोतरी एक वास्तविकता है:** छत्तीसगढ़, देश के कई अन्य राज्यों की तरह, बच्चों और महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों में भी एनीमिया के बिगड़ते स्तर से जूझ रहा है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के तरीकों से इसे व्यापक, प्रभावी, सुरक्षित और स्थायी रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है।

2. **<u>भारत सरकार की चावल फोर्टिफिकेशन योजना:</u>** वर्ष 2021 से भारत में बड़े पैमाने पर फोर्टिफाइड चावल का उत्पादन और वितरण शुरू किया गया है, जबकि भारत के 15 राज्यों के 15 जिलों में 3 साल की पायलट योजना की शुरुआत 2019 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। सभी 15 राज्यों में योजना के अनुसार पायलटों को शुरू करने से पहले, 11 राज्यों में पायलटों को पूरा करने के पूर्व, अथवा उनके मूल्यांकन से पहले या सार्वजनिक डोमेन में विशेषज्ञ जांच के लिए निष्कर्ष निकाले जाने से पहले, अनुचित रूप से अप्रैल 2022 तक देश के 257 जिलों में स्केलिंग शुरू हो गई थी।

3. **<u>छत्तीसगढ़ बिना किसी वैज्ञानिक आधार के एफआर उत्पादन और वितरण में सबसे आगे है:</u>**

छत्तीसगढ़ इस चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम में सबसे आगे रहा है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि अन्य नवीन समग्र पोषण हस्तक्षेप राज्य में भी चल रहा है। ऐसे कारणों से फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम अस्पष्ट और यहां तक कि अस्तित्वहीन दिखाई देता हैं। कोंडागांव में पायलट अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी। इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है और न ही तीन साल के समय को पूरा किया गया। हालाँकि, भारत में फोर्टिफाइड चावल वितरण का सबसे बड़ा अनुपात (25-45%) अभी छत्तीसगढ़ में हो रहा है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय संचालन समिति चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम को चलाने और सुव्यवस्थित करने के लिए काम कर रही है। इस समय अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं देती है)। इसके अलावा, राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए आवंटित पर्याप्त बजट (लगभग 45 करोड़ रुपये) खर्च कर रही है और यह राज्य में लक्षित सूक्ष्म पोषक पूरक कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त आवंटन से काफी अधिक है। ऐसा लगता है कि यह भारत सरकार के दबाव में हो रहा है।

4. **<u>पूरी कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग की गैर मौजूदगी</u>** : राष्ट्रीय स्तर की तरह छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भूमिका स्पष्ट नहीं है. हालांकि एनीमिया एक सार्वजनिक वितरण विभाग के नेतृत्व में एफआरके सम्मिश्रण और फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की व्यवहार्यता या रसद का मामला न रहकर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य भारत के संविधान के अनुसार राज्य का विषय है।

5. **<u>चावल की पौष्टिकता प्रभावी नहीं है - यह सुरक्षा के मुद्दे भी हैं:</u>** एनीमिया से निपटने के लिए चावल फोर्टिफिकेशन एक प्रभावी रणनीति के रूप में न तो भारत में और न ही दुनिया में अन्य जगहों पर नहीं पाई गई है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एजेंसी के आरटीआई जवाबों, प्रकाशित पत्रों और प्रकाशित सामग्रियों की विश्वसनीय समीक्षाओं से स्पष्ट है। इस रणनीति में जहां प्रभावकारिता, अनुचित लागत और सप्लाई श्रृंखला में अपरिवर्तनीय परिवर्तन पर अनुत्तरित प्रश्न हैं, वहीं सभी नागरिकों के लिए फोर्टिफाइड चावल की सुरक्षा और विनियमन से संबंधित गंभीर प्रश्न भी हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (2018 के एफएसएसएआई विनियम) द्वारा अधिसूचित वैधानिक नियम हैं जिनका पालन सभी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों द्वारा किया जाना है, जिसमें सरकारी खाद्य योजनाओं में शामिल एजेंसियां भी शामिल हैं। थैलेसीमिया के रोगियों को केवल चिकित्सकीय देखरेख में आयरन-फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का सेवन करने और सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन न करने की चेतावनी देनी चाहिए। इसके साथ ही लेबल स्पष्ट होने चाहिए।

6. **छत्तीसगढ़ में विपरीत-संकेत शर्तों का उच्च रोग भार है:** छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को राज्य में मौजूदा बीमारी के बोझ, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया, को देखते हुए अपने

नागरिकों के बीच फोर्टिफाइड चावल के वितरण के बारे में (अधिक) चिंतित होना चाहिए। पूर्व की दो चिकित्सा स्थितियों की कोई व्यापक जांच मौजूद नहीं है और सिकल सेल विकारों पर सूक्ष्म अध्ययन और स्क्रीनिंग परियोजनाओं से लगभग 0.2-0.6% में जांच किए गए व्यक्तियों और सिकल सेल रोग के लगभग 9-10% (एएस) के सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। अनुमान है कि राज्य में कम से कम 1.5 लाख लोग एससीडी से पीड़ित हैं। 2014 में सात जिलों को कवर करने वाले एक सूक्ष्म अध्ययन में, लगभग 18% जांच की गई आबादी में थैलेसीमिया वाहक पाया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया है कि भारत के लगभग 18% मलेरिया के मामले कुछ वर्षों में अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। टीबी का प्रसार भी अधिक है, 2021-22 में लगभग 32500-विषम मामलों के साथ।

7. **<u>लौह युक्त-फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के खिलाफ चिकित्सा कारण मौजूद हैं:</u>** चिकित्सा विज्ञान से पता चलता है कि एससीडी रोगियों के मामले में, लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर सिकल के आकार की कोशिकाएं आसानी से टूट जाती हैं, जिससे संचलन में लौह तत्व निकलता है; लाल रक्त कणिकाओं (आरबीसी) के नियमित विनाश के परिणामस्वरूप शरीर में लौह तत्व के भंडार का निर्माण होता है और इससे लीवर खराब हो सकता है। फोर्टिफाइड चावल लोहे के भंडार को जोड़ता है जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार संभावित रूप से लौह के अधिभार और अंग (यकृत, अंतःस्रावी तंत्र, हृदय) को नुकसान होता है। थैलेसीमिया में, बार-बार रक्त चढ़ाने से लौह तत्व की अधिकता बढ़ जाती है, जिससे हृदय की क्षति, लिवर फाइब्रोसिस, प्रजनन संबंधी समस्याएं और विकास मंदता हो जाती है। लौह युक्त फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ यहां भी वर्जित हैं।

8. **<u>आदिवासी इस दृष्टिकोण में अनुपातहीन रूप से कमजोर हैं:</u>** आदिवासी भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% हैं, छत्तीसगढ़ में, वे आबादी का 30.6% (जनगणना 2011) बनाते हैं। 2011 की जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में 18 जिलों में से कम से कम 9 जिले थे, जहां कुल आबादी का 40% से अधिक आदिवासियों का था। यह ऐसा आदिवासी वर्ग है जो अन्य जातीय समूहों की तुलना में एससीडी और थैलेसीमिया जैसे आनुवंशिक विकारों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। यह आदिवासी समुदाय भी हैं, जिन पर कई तरह के नुकसान और कमजोरियां हैं, जो सरकारी खाद्य योजनाओं से अपने अधिकारों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

9. **<u>प्रमुख निष्कर्ष</u>: इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष हैं:**

a. <u>प्रारम्भ से ही सामुदायिक अस्वीकृति:</u> फैक्ट-फाइंडिंग के दौरान, कई स्थानों पर टीम ने पाया कि, समुदायों ने शुरू में फोर्टिफाइड चावल को काफी दृढ़ता से खारिज कर दिया था। जबकि इनमें से कुछ "प्लास्टिक चावल" के आसपास की आशंकाओं से जुड़ा हुआ है, कुछ इसमें वरीयता की कमी थी। एक स्थान पर, यह प्रतिकूल प्रभाव था जिसने समुदाय को फोर्टिफाइड चावल की खपत को छोड़ दिया। कोंडागांव क्षेत्र के दौरे में, टीम ने पाया कि पीडीएस लाभार्थियों ने एक महीने के लिए फोर्टिफाइड चावल खरीदने से इनकार कर दिया। लौह-युक्त खाद्य पदार्थों से संबंधित किसी भी संदेश के बिना फोर्टिफाइड चावल के गुणों के बारे में आक्रामक प्रचार द्वारा राज्य सरकार द्वारा इसे दूर करने की मांग की जा रही है।

b. **<u>FRK को अब भी अलग किया जा रहा है:</u> फैक्ट-फाइंडिंग करने वाली टीमों ने पाया कि अब भी, बड़ी संख्या में लोग PDS आपूर्ति में FRK मिश्रित प्राकृतिक चावल खाने से बचते हैं। कम से कम 3 तरीके हैं जिनसे रासायनिक दुर्गन्ध दूर हो रहे हैं - एक, सफाई के चरण के दौरान हाथ से उठाकर जहां महिलाएं रंग और रूप से FRK को पहचानने में सक्षम होती हैं; दूसरा, जब चावल पानी में भिगोया जाता है तब FRK ऊपर तैरता है, तो उसे हटा दिया जाता है; तीसरा, जब चावल पकने के बाद अतिरिक्त पानी निकल जाए। यह लाभार्थियों के घरों के साथ-साथ आंगनबाड़ियों में भी हो रहा है। यह इस दृष्टिकोण की प्रभावकारिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, इसके अलावा यह डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य के अवलोकन से पता चलता है कि अन्य चिकित्सा कारणों से भी प्रभावकारिता संबंधी प्रश्न उठते हैं।**

C. **<u>फोर्टिफाइड चावल के सेवन के बाद दर्ज की गई प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं:</u> दौरे के दौरान, कुछ लोगों की ओर से कुछ स्थानों पर प्रतिकूल शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी मिलीं। पेट दर्द आम शिकायत सुनी गई थी; हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या फोर्टिफाइड चावल इसका कारण था।**

d. **<u>बगैर सूचित किए लोगों को अंधाधुंध व गैरजिम्मेदार तरीके से वितरित किया जा रहा है आयरन फोर्टिफाइड चावल:</u> गैर-संकेतित रोगियों को भी फोर्टिफाइड चावल का अंधाधुंध वितरण होता है - यहां, कई मुद्दे सामने आते हैं। (i) सिकल सेल रोग व्यक्तियों और थैलेसीमिया रोगियों की पहचान करने के लिए जनसंख्या की कोई व्यापक जांच नहीं की गई है। इसलिए, किसी भी चिकित्सा सलाह का पालन करने वाले रोगियों का सवाल ही नहीं उठता है; (ii) यहां तक कि जिन रोगियों की पहचान की गई है, वे भी फोर्टिफाइड चावल का सेवन कर रहे हैं क्योंकि किसी ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी नहीं दी थी; (iii) कई मामलों में, रोगियों के पास उनकी**

गरीबी की स्थिति को देखते हुए आयरन फोर्टिफाइड चावल खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है; (iv) भले ही हर घर को फोर्टिफाइड और नॉन-फोर्टिफाइड दोनों तरह के चावल की आपूर्ति अलग-अलग की जाती है, घर के खाना पकाने के तरीकों में इस अंतर को बनाए रखना, जहां हर दिन दो तरह के चावल पकाना संभव नहीं हो सकता है; (v) भले ही यह वास्तव में उन घरों में अधिक काम करने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है जहां खाना पकाने को उनकी लैंगिक जिम्मेदारी बना दिया गया है, ऐसे विकल्प आंगनवाड़ी और स्कूल के भोजन में संक्रमित व्यक्तियों के लिए मौजूद नहीं हैं।

e. **<u>सांविधिक खाद्य सुरक्षा विनियमों का पालन न करना:</u> टीमों ने यह भी पाया कि लौह-फोर्टिफाइड चावल के संबंध में वैधानिक लेबलिंग नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। F+ लोगो हमेशा नहीं होता था, और न ही सभी मामलों में चेतावनी के बयानों को स्टेंसिल और लेबल किया जाता था। इसके अलावा, लेबलिंग अधूरी थी, जहां यह मौजूद थी। महत्वपूर्ण रूप से, लेबलिंग नियमों के अनुपालन का इस मामले में विभिन्न कारणों से अंतिम उपभोक्ता के लिए कुछ खास मायने नहीं रखता है - छत्तीसगढ़ में, पीडीएस डीलरों, आंगनवाड़ी और स्कूलों को बोरियों को वापस करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें सरकारी खाद्य योजनाओं के लिए चावल की आपूर्ति की गई है। इस तरह के चावल को किसी भी बैग में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उस चरण से कंटेनर में आपूर्ति की जाती है और आपूर्ति की गई बैग वापस कर दी जाती है। उस स्तर से, उस अर्थ में, लेबलिंग का कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा, अंतिम उपभोक्ताओं को उनकी आपूर्ति ढीले में मिलती है, न कि पैकेज्ड लेबल वाले तरीके से। गरीबी, साक्षरता और विपरीत परिस्थितियों के बारे में ज्ञान ऐसा है कि भले ही सभी मुद्दों को संबोधित किया गया हो, मरीज फोर्टिफाइड चावल से बचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।**

f. **<u>सरकार द्वारा एकतरफा गलत प्रचार</u>: फैक्ट-फाइंडिंग टीमों ने पाया कि गढ़वाले चावल के संभावित लाभों को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दीवार-लेखन, पोस्टर, बैनर, समाचार पत्र विज्ञापन आदि के रूप में बढ़ाया गया था; दूसरी ओर, पीडीएस डीलरों, आंगनबाडी पदाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति के बारे में नहीं बताया गया और न ही कोई चेतावनी बयान दिया गया. भले ही भोजन के रूप में महत्वपूर्ण अपने भोजन को जानने का अधिकार और सूचित विकल्पों का अधिकार बुनियादी अधिकार हो, इस तरह के बड़े पैमाने पर वितरण शुरू होने से पहले लाभार्थियों से कोई पूर्व सूचित सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।**

g. **<u>सुरक्षा मानकों की कमी एवं बिना जानकारी के छत्तीसगढ़ सरकार अन्य राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति अधिक फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है</u>** : छत्तीसगढ़ में, प्रति व्यक्ति पीडीएस-आधारित पात्रता अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, और सभी योजनाएं (पीएमजीकेएवाई सहित) अभी केवल फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही हैं। चुने हुए जिलों में इससे लौह तत्व की अधिक खुराक हो सकती है।

h. **<u>कई हस्तक्षेपों की लेयरिंग से संभावित आयरन ओवर-डोजिंग भी होती है:</u>** छत्तीसगढ़ में अन्य योजनाएं भी हैं जो कुपोषण को दूर करने की कोशिश करती हैं, इस तथ्य के अलावा कि यह अपने नागरिकों को अधिक मात्रा में गढ़वाले चावल की आपूर्ति कर रहा है। इसमें फोर्टिफाइड टेक होम राशन शामिल है, जिसमें संयोग से आयरन भी मिला हुआ है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व पूरक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। कुछ जिलों में पीडीएस में गुड़ और चना की आपूर्ति की जाती है। कमजोर आबादी के लोहे की अधिक खुराक के जोखिम की जांच के लिए व्यापक रूप से सभी हस्तक्षेपों का कोई मूल्यांकन नहीं है।

i. **<u>सरकारी पदाधिकारियों के बीच भी चिंताएं:</u>** यह उल्लेखनीय है कि जब हस्तक्षेप से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई तब फैक्ट-फाइंडिंग टीमों को केवल सरकार में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं और आपत्तियों का सामना करना पड़ा है। चावल के फोर्टिफिकेशन के बारे में बहस और जानकारी की कमी चौंकाने और परेशान करने वाली है।

10. **<u>छत्तीसगढ़ में पोषण को संबोधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिनव विकल्पों की संभावना है:</u>** उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सरकार और जिला प्रशासन द्वारा किए गए समग्र अभिनव हस्तक्षेप हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना समग्र है, जिसमें हस्तक्षेप के साथ इकाई लागत मानदंड उपयुक्त हैं। एनजीजीबी और गोधन न्याय योजना में दूध की आपूर्ति के अलावा मिट्टी के पोषण और पौधों के पोषण में सुधार के माध्यम से मानव पोषण में सुधार करने की क्षमता है। गर्म पके हुए भोजन में शामिल अंडे और दाल एक अतिरिक्त तरीका है। राज्य में मिलेट मिशन उड़ान भरने वाला है। परंपरागत रूप से, छत्तीसगढ़ पोषक तत्वों से भरपूर विविध स्थानीय खाद्य पदार्थों का भी घर है, जिनमें अकृषि वन खाद्य पदार्थ और साग शामिल हैं, जिन्हे इन्हें खेतों और प्लेटों में पुनर्जीवित करने के लिए निवेश किया जाना चाहिए। वन खाद्य पदार्थों सहित अकृषि खाद्य पदार्थों की अधिकता के मामले में भी ऐसा ही है। कठिन परिश्रम को कम करने के लिए किए गए सुधारों के साथ पारंपरिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां नागरिकों को पौष्टिक अर्ध-पॉलिश किए गए अनाज और तेल की आपूर्ति की जा सकती हैं। फिर भी, यह स्पष्ट नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार, जो कई हस्तक्षेपों में सही नीतिगत दृष्टिकोण प्रदर्शित करने के बावजूद, फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन और वितरण को इतनी तेजी से क्यों बढ़ा रही है।

11. **<u>निष्कर्ष और प्रमुख सिफारिशें:</u> इस अन्वेषण के दौरान नोट की गई उपरोक्त चिंताओं को देखते हुए और कुपोषण को दूर करने के लिए सुरक्षित, प्रभावी, टिकाऊ और समुदाय-नियंत्रित विकल्प मौजूद हैं, आशा और आरटीएफसी ने सिफारिश की है कि छत्तीसगढ़ सरकार को भारत सरकार द्वारा मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और राज्य सरकार को राज्य में फोर्टिफाइड चावल का वितरण तुरंत बंद कर देना चाहिए।**

<u>अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें</u>:

Kavitha Kuruganti, ASHA-Kisan Swaraj at 8880067772

Sangeeta Sahu, Right To Food Campaign Chhattisgarh at 9993637787

Dr. Randall Sequeira, Public Health Practitioners at 9829477656

Raj Shekhar, Right To Food Campaign National Secretariat at 7985946875